AIDWA

जुलाई, 2022
न्यूज़ लैटर

1. संपादकीय
2. फासीवादी ताकतों के हमले से भारत की रक्षा करने की जरूरत

-मरियम ढवले (राष्ट्रीय महासचिव, एडवा)

3. अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, हरियाणा का 11वां राज्य सम्मेलन सम्पन्न

- सविता (राज्य महासचिव, जनवादी महिला समिति हरियाणा इकाई)

4. भोपाल में अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क सम्मेलन
5. नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम .. उप्र एडवा का सद्भावना अभियान

- मधु गर्ग (केंद्रीय कमेटी सदस्य, एडवा)

6. 'रेत समाधि' – एक उपन्यास जो सीमाओं को तोड़ता है

- मनजीत राठी

7. खेल और विश्व विजेता निखत

- जगमती सांगवान

संपादकीय

सुभाषिनी अली

(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एडवा)

पिछले हफ्तों की घटनाओं ने भारत की न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिये हैं। जून 24 को सर्वोच्च न्यायालय ने जकिया जाफरी, जिनके पति, एहसान जाफरी, कांग्रेस के पूर्व सांसद, को गुजरात दंगों के दौरान 60 से अधिक लोगों के साथ जिंदा जला दिया गया था, की न्याय की गुहार को खारिज कर दिया। जाकिया जाफरी, 2002 से लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। उनका आरोप रहा है की गुजरात के उस समय के मुख्य मंत्री, नरेंद्र मोदी, ने जान बूझकर एहसान जाफरी और उनके पड़ोसियों पर दंगाइयों द्वारा किए जा रहे हमले मे किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इंकार किया। एहसान जाफरी ने कई बार उनसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उन्होने उनकी एक न सुनी। अंत में, एहसान जाफरी और उनके कई पडोसियों को जिंदा जला दिया गया। इस बार्बर कांड के मुख्य आरोपी, गुजरात की मंत्री माया कोदनानी और बाबू बजरंगी कुछ साल जेल मे रहने के बाद, जमानत पर छोड़ दिये गए थे।

जकिया जाफरी हर स्तर पर न्याय की लड़ाई लड़ती रही हैं। उनका आरोप है की उनके पति और अन्य लोगों की हत्या के लिए नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार हैं। उनकी इस लड़ाई मे उनका साथ तीस्ता सीतलवाद दे रही थी। हमारे देश के मानव अधिकारों की रक्षा की लड़ाई मे तीस्ता का ही नाम सबसे ऊंचे पद पर है। उन्होने 1990 मे मुंबई मे हुए दंगों मे दंगा पीड़ितों के पक्ष मे जबरदस्त लड़ाई लड़ी और गुजरात दंगों के पीड़ितों के संघर्ष मे उनका योगदान अनोखा रहा है। उनके हस्तक्षेप ने कई लोगों को न्याय भी दिलाया है। नतीजे के तौर पर, तीस्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसों की आँख की किरकिरी बन गईं। उसके खिलाफ तमाम मुकद्दमे दर्ज किए गए। उस पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया लेकिन उसको न्यायपालिका ने निर्दोष ही ठहराया।

24 जून को उसी सर्वोच्च न्यायालय ने जाकिया जाफरी की अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उसने एसआईटी के बयान पर किसी तरह के सवाल–जवाब किए बगैर, उसे पूरी तरह से सही माना। यही नहीं, न्यायाधीशों ने न्याय के लिए लड़ने वालों पर तीखी टिप्पणियाँ की, उन्हे साजिश का हिस्सा ठहराया और, चंद शब्दों मे, उन्हे दंडित करने की बात भी की। यह अपने आप मे बिलकुल ही उचित नहीं है। न्याय मांगना और न्याय के लिए लड़ना हमारा मूलभूत अधिकार है। अगर उसे छीन लिया जाता है तो संविधान और कानून के संरक्षण से तमाम नागरिक वंचित हो जाएँगे। वैसे भी हमारे देश मे गरीब और

आम लोगों के लिए न्याय का हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। अगर इसकी तलाश पर नियंत्रण लगा दिया जाएगा तो फिर यह असंभव हो जाएगा।

25 तारीख को, सुबह–सुबह, गुजरात की पुलिस ने तीस्ता को उसके मुंबई–स्थित निवास से गिरफ्तार कर लिया। कमाल की तत्परता दिखाई गई। 24 की शाम को ही सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और 25 की सुबह तक सारी कार्यवाहियाँ करके, गुजरात की पुलिस मुंबई पहुँच गयी। तीस्ता के साथ हाथा–पाई भी हुई और उसे अहमदाबाद लाकर जेल भेज दिया गया। उसके साथ पूर्व गुजरात के पूर्व डी जी पी, श्रीकुमार, और पूर्व डीजीपी संजीव भट्ट को भी आरोपी बनाया गया है। भट्ट तो पहले से ही जेल मे हैं, अब श्रीकुमार भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।

न्यायपालिका के न्याय के बारे मे क्या कहा जाये? बाबू बजरंगी और माया कोदनानी जिनके हाथ खून से रंगे हैं, जिनको न्यायालय ने दंगे मे शामिल होने का दोषी माना है, वे आजाद घूम रहे हैं और बहादुर लड़ने वाली तीस्ता जेल के अंदर है!

यही नहीं झूठी खबरों का पर्दाफाश करने वाले मोहम्म्द जुबैर को भी इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ उनके 2018 की ट्वीट को लेकर आरोप लगाया गया की उन्होने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। दरअसल, जुबैर ने 1987 मे ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा बनाई फिल्म के एक 'क्लिप' को शेर किया था जिसमे 'हनीमून होटल' का नाम 'हनुमान होटल' मे बदल गया। इस बेबुनियाद आरोप के आधार पर उन्हे जेल भेज दिया गया है। याद करने की बात है की जुबैर ने नूपर शर्मा के आपत्तीजनक टिप्पणी को साझा किया था और वह लगातार संघियों की झूठी बातों का भी खुलासा करते रहे हैं। इसलिए वह जेल मे हैं जबकि नूपुर शर्मा अब भी आजाद घूम रही हैं। उनके खिलाफ पिछले हफ्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने जबरदस्त बातें की लेकिन वह बस बातें ही रेह गईं।

देश भर और विदेशों मे भी इन दोनों गिरफ्तारियों की जबरदस्त आलोचना हुई है लेकिन हमारी सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं पेश किया गया है। बल्कि उसने संविधान की समाप्ती की ओर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने का काम किया है।

एडवा की तमाम इकाइयों ने तीस्ता के साथ हुई ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई, प्रदर्शन किया और जुलूस निकाले। तीस्ता का हमारे संगठन के साथ बहुत करीबी रिश्ते हैं। हमने हमेशा उसके काम को सराहा है और उसके सहयोग मे जूटे हैं। आज भी हम उसके साथ खड़े हैं।

हमारा देश आज काले बादलों से घिरा है। हमारे तमाम अधिकार हमसे छिनते जा रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। हमे आगे बढ़कर इन चुनौतियों को स्वीकार करना होगा।

फासीवादी ताकतों के हमले से भारत की रक्षा करने की जरूरत

मरियम ढवले

यह कोई संयोग नहीं है कि तीस्ता सीतलवाड़ को इस साल 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को 2002 के गुजरात सांप्रदायिक नरसंहार के पीड़ितों के लिए न्याय के लिए लड़ना जारी रखने ''दुस्साहस'' के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया गया। उसे और अन्य लोगों को दमन के आगे घुटने नहीं टेकने और न्याय के झंडे को उंचा उठाये रखने के लिए दंडित किया जा रहा है। सैंतालीस साल पहले, 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आपातकाल की घोषणा की थी। इस देश ने उस वक्त लोकतंत्र की क्रूर पकड़ का अनुभव किया था, जिसमें हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जेल में डाल दिया गया था।

अब हम अपने देश में ''अघोषित आपातकाल'' का सामना कर रहे हैं। कई कार्यकर्ता बिना किसी राहत के जेलों में बंद हैं। उन्हें लगातार जमानत देने से इनकार किया जा रहा है। भाजपा–आरएसएस और संघ परिवार के नेता जो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले और हत्या की मांग कर रहे हैं, बहुसंख्यक समुदाय को हिंसा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, वे स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं।

मोदी सरकार की कारपोरेट समर्थक नीतियों पर सवाल उठाने और विरोध करने वालों का मजाक उड़ाया जाता है और उन्हें ''राष्ट्र–विरोधी'' करार दिया जाता है। धर्मनिरपेक्ष भारत का समर्थन करने वाले नागरिकों की निंदा की जाती है और उन्हें भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया जाता है। संसद सहित सभी संवैधानिक संस्थाओं और हमारे संविधान द्वारा हमें दिए गए अधिकारों को जानबूझकर नष्ट किया जा रहा है।

गरीब लोग बड़े पैमाने पर मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और भुखमरी से जूझ रहे हैं। हिंसा महिलाओं के जीवन को बेहद असुरक्षित बना रही है। दलितों और मुसलमानों पर हमले किसी भी दंडात्मक कार्यवाही के न किये जाने के आश्वासन के साथ किए जाते हैं। राजनीतिक लामबंदी के लिए धर्म और जाति के उपयोग से लोगों का ध्रुवीकरण हुआ है। इसने चुनावी मुनाफे के लिए नफरत की राजनीति के बड़े पैमाने पर और स्पष्ट उपयोग को प्रोत्साहित किया है।

यह बहुत खतरनाक समय हैं। सत्ता में मौजूद फासीवादी ताकतें भारत के चरित्र को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से एक ईश्वरशासित, सत्तावादी, मनुवादी राज्य में बदलना चाहती हैं। अब समय आ गया है कि देश के सभी नागरिक इन प्रतिगामी शक्तियों का विरोध करने और उनका मुकाबला करने के लिए एक साथ आएं। जैसा कि हम अपनी आजादी के 75 साल पूरे होने के करीब हैं, हमें संकल्प लेना चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में –

जहां मन भय के बिना है और सिर ऊंचा उठा हुआ है।

जहां ज्ञान, मुक्त है।

जहां दुनिया को संकीर्ण छोटी छोटी दीवारों द्वारा टुकड़ों में बांटा नहीं गया है।

जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हैं।

जहां अथक प्रयास दोषहीन पूर्णता तक ले जाते हैं।

जहां उद्देश्य की स्वच्छ धारा सडी गली आदतों की नीरस रेगिस्तानी रेत में खोई नहीं है।

जहां मष्तिष्क की पहुंच अथांग और असीमित विचारों और उन्हे वास्तविकता में उतारने वाली क्रियाओं तक है – स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, मेरे पिता, मेरे देश की नींद को टूटने दो !

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, हरियाणा का 11वां राज्य सम्मेलन सम्पन्न

सविता

(राज्य महासचिव, जनवादी महिला समिति हरियाणा इकाई)

जनवादी महिला समिति हरियाणा का दो दिवसीय 11वां राज्य सम्मेलन 25–26 जून को करनाल के पंचायत भवन में हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में मंहगाई, खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी महिलाओं बढ़ती हिंसा, गांवों व शहरों में बढ़ती शराब व नशे की खपत, शिक्षा, स्वास्थ्य, साम्प्रदायिकता व जातिवाद की चुनौतियों, पितृसतात्मक मानसिकता तथा नवउदारवादी नीतियों के प्रभावों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान किया गया। सम्मेलन में विभिन्न तबकों की महिलाओं के संघर्षों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए उनके बीच में काम बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया।

खुला अधिवेशन

सम्मेलन की शुरूआत स्थानीय फव्वारा पार्क में खुले अधिवेशन के साथ की गई। खुले अधिवेशन में शहर के गणमान्य नागरिकों के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। खुले अधिवेशन की अध्यक्षता राज्य अध्यक्षा उषा सरोहा ने की। खुले अधिवेशन में जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय महासचिव मरियम ढ़वले, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद सुभाषिनी अली सहगल और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमति सांगवान ने सम्बोधित किया। जनवादी महिला समिति की राज्य महासचिव सविता ने संचालन किया। स्वागत समिति की अध्यक्षा व एलआईसी की महिला सब कमेटी की संयोजक पुष्पलता, स्वागत समिति की संरक्षक व सर्व कर्मचारी संघ की नेता शारदा, संरक्षक पार्वती तनेजा, राज्य कोषाध्यक्ष राजकुमारी दहिया,

उपाध्यक्ष शकुन्तला जाखड़, रामकली जांगड़ा, सहसचिव अंजू, करनाल जिला की सचिव जरासो भी मंच पर उपस्थित रहीं।

सम्मेलन के खुले सत्र का उद्घाटन करते हुए जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद सुभाषिनी अली सहगल ने कहा कि करनाल जिला का नाम कल्पना चावला के नाम से जुड़ा होने के करण पुरे विश्व में विख्यात है। कल्पना चावला ने मानव जाति के विकास के लिए विज्ञान की खोज में अपना जीवन समर्पित किया। लेकिन कुछ लोग जनता में वैज्ञानिक सोच ना आ जाए, इसके लिए प्रयासरत हैं। लगातार अंधविश्वास, पांखड़, तर्कहीनता, पिछड़ेपन, रूढ़िवाद, भाग्यवाद, कर्मकांड को बढ़ाया जा रहा है और सता के संरक्षण में लोगों को वैज्ञानिक सोच से दूर किया जा रहा है। हमें कल्पना चावला को याद करते हुए अंधविश्वास के अंधकार को निकालकर वैज्ञानिक सोच आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमें उन स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं को याद करना होगा जिन्होंने उस समय तमाम बन्धनों को तोड़कर आजादी के आंदोलन में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया। जनवादी महिला समिति की संस्थापक ज्यादातर संस्थापक नेता स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। हमें उनके योगदान को जनता के बीच में ले जाना होगा। उन्होनें कहा कि साल भर चले किसान आंदोलन में हरियाणा की महिलाओं का अतुलनीय योगदान है। उन्होनें ना सिर्फ अपने घरों को सम्भाला बल्कि बॉर्डर्स व टोल प्लाजाओं पर चल रहे धरनों में रसद पंहुचाने, भीड़ जुटाने व नेतृत्व देने का काम भी किया। महिलाओं ने साबित किया किया कि वे किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं हैं। हरियाणा की महिलाओं ने दिखाया कि वे अगर ठान लें तो जो काम जिम्मे लेती हैं, उसे करके ही छोड़ती हैं। किसान आंदोलन से सबक लेते हुए हमें अपने संगठन को मजबूत करते हुए देश के सामने मिसाल कायम करनी होगी।

जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय महासचिव मरियम ढवले ने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में कहा कि डा. भीम राव अम्बेडकर ने सबको समानता का अधिकार देने के लिए संविधान की रचना की थी। मौजूदा सरकार मौजूदा सरकार लगातार महिलाओं के सवैंधानिक अधिकारों को

छीनने के प्रयास कर रही है। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद महिलाओं के सामने नए खतरे व चुनौतियों खड़ी कर दी हैं। मनुस्मृति लागू करके औरतों को वापिस घरों की चारदिवारी में धकेलने की तैयारी है। धर्म और जात के नाम पर पुरे देश का चरित्र बदलने का प्रयास हो रहा है। नफरत की राजनीति की जा रही है। केन्द्र सरकार की नवउदारवादी नीतियों व कोरोना महामारी की बदइंतजामी के महिलाओं पर बहुत खतरनाक प्रभाव पड़े हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में बेरोजगारी व गरीबी की दिशा में धकेल दी गई हैं। देश में मंहगाई, कुपोषण और भूखमरी बढ़ रही है। सार्वजनिक संपतियो को सरकार द्वारा लगातार बेचा जा रहा है और देश की अर्थव्यवस्था तहस–नहस की जा रही है। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि हमें पूरी खाद्य सुरक्षा व रोजगार हासिल करने के लिए अपने संघर्षो को और ज्यादा मजबूती देनी होगी।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमति सांगवान ने कहा कि हरियाणा में पिछले 35 सालों से संघर्ष कर रही जनवादी महिला समिति ने मुख्यमंत्री को आईना दिखाने के लिए यहां सम्मेलन का आयोजन किया है। हरियाणा में मंहगाई व बेरोजगारी चरम पर है। सामाजिक क्षेत्र के खर्चों में कटौतियां हैं। सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली, मनरेगा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कम किया जा रहा है व बड़े–बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। पिछले आठ सालों में नए राशन कार्ड बनाना तो दूर बल्कि पीले व गुलाबी राशन कार्डों में कटौती की गई है। हमारे संगठन की मांग है की पीडीएस का बजट बढ़ाया जाए तथा केरल प्रदेश की तर्ज पर पीडीएस को सार्वभौमिक बनाया जाए , गेहूं चावल व मोटे अनाज की मात्रा अधिक की जाए व खाद्य तेल, शक्कर, दालें समेत चौदह चीजें उपलब्ध कराई जाए। केरल की तरह हरियाणा में भी 100 दिन का रोजगार गांरटी कानून शहरों में भी लागू किया जाए। उन्होंनें यह भी कहा कि इस परिस्थिति में हरियाणा में महिलाओं ने रिकॉर्डतोड़ आंदोलन किए हैं। 4 महीने तक चला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन व किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय रही है। इसलिए हमें अपनी कतारों को बढ़ाना होगा व हर गांव–मोहल्ले तक अपनी आवाज पंहुचानी होगी। खुले अधिवेशन में किसान आंदोलन व आंगनवाड़ी आंदोलन को उनके संघर्ष के लिए सम्मानित भी किया गया। श्रोताओं ने तालियों की गड़गडाहट के साथ उनके संघर्ष को सराहना की व एकजूटता प्रकट की। जनवादी महिला समिति की राज्य अध्यक्ष उषा सरोहा ने सबको धन्यवाद देते हुए खुले सत्र का समापन किया।

प्रतिनिधि सत्र

प्रतिनीधि सत्र की शुरूआत राज्याध्यक्ष उषा सरोहा ने झंडा फहराकर की। सम्मेलन स्थल पर नगर का नाम तेलगांना सशस्त्र संघर्ष की नेत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी व जनवादी महिला समिति की संस्थापक नेताओं में से एक मल्लू स्वराज्यम, हॉल का नाम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व संरक्षक मैथिली शिवरामन व संस्थापक नेताओं में से एक व पूर्व सांसद विभा घोष गोस्वामी तथा मंच का नाम रोहतक जिला की जुझारू साथी व संस्थापक नेताओं में से एक महाकौर

को समर्पित किया गया। सभी प्रतिनिधियों ने उन्हें व अन्य शहीदों को फूल अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि पेश की।

स्वागत समिति की अध्यक्षा पुष्पलता ने सभी प्रतिनिधियों व मेहमानों का स्वागत किया। उन्होनें स्वागत करने के साथ–साथ करनाल जिले के ऐतिहासिक महत्व, यहां के आंदोलनों के इतिहास और एलआईसी का नीजिकरण करने की सरकार की नापाक कोशिशों के बारे में भी बताया। राज्य कमेटी सदस्य अमिता ने शोक प्रस्ताव पेश किया और प्रतिनिधियों ने दो मिनट मौन रखकर दिवगंत नेताओं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

बिरादराना संगठनों के नेताओं ने सम्मेलन को अपनी शुभकामनाएं दी। सर्व कर्मचारी संघ के राज्य महासचिव सतीश सेठी, सी.आइ.टी.यू. के राज्य महासचिव जयभगवान, एस.एफ.आई. के राज्य सचिव मनजीत, खेत मजदूर युनियन के राज्याध्यक्ष जगमाल सिंह, विकलांग अधिकार मंच के राज्य महासचिव ऋषिकेश राजली, किसान सभा की नेता डिंपल ने शुभकामना संदेश देते हुए सांझे संघर्षो की जरूरत पर बल दिया।

राज्य महासचिव सविता ने राजनैतिक व सांगठनिक रिपोर्ट का मसौदा पेश किया। रिपोर्ट में पेश करते हुए उन्होंने कहा कि यह दौर सभी प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष व लोकतान्त्रिक ताकतों की तरह महिला आंदोलन के लिए बेहद भी चुनौतीपुर्ण है। परन्तु इन तीन सालों में यह चुनौती जितनी ज्यादा विकराल हुई है, उतनी ही सम्भावनाएं भी खुली हैं। एक तरफ जहां भाजपा सरकार आरएसएस की सरपरस्ती में नवउदारवादी–साम्प्रदायिक नीतियों को ताबड़तोड़ ढंग से लागू करते हुए देश को हिन्दूत्ववादी राज्य बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रही है, वहीं इन नीतियों और कोरोना महामारी के कुप्रंबधन की मार झेल रही जनता में आक्रोश भी उतनी तेजी से बढ़ रहा है। भाजपा सरकार के लोगों को आपस में बांटने व मुद्दों से ध्यान भटकाने के तमाम हथकंडों के बावजूद विभिन्न मुद्दों पर संगठित व स्वतःस्फूर्त ढ़ंग से सशक्त जनआंदोलन उभर रहे हैं और तानाशाही सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐतिहासिक किसान आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसकी सफलता ने सभी जनांदोलनों में ना सिर्फ नई उर्जा का संचार किया है बल्कि सभी लोकतान्त्रिक ताकतों के लिए बड़ी जगह खोल दी है। इन आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी शानदार हैं। वे ना सिर्फ इन आंदोलनों में बड़ी संख्या में शामिल हैं बल्कि अगुवाई भी कर रही हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग की महिलाओं का बेमिसाल संघर्ष व किसान आंदोलन में महिलाओं की शानदार भागीदारी इसके दो खुबसुरत उदाहरण हैं। इस समय जब तमाम प्रतिगामी ताकतें सता के संरक्षण में महिलाओं को वापिस घरों में धकेलना चाहती हैं, महिलाओं ने उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए इन दोनों आंदोलनों में कंपकंपाती सर्दी, गर्मी, बारिश को झेलते हुए खुले आसमान के नीचे सड़कों को अपना घर बना लिया। पितृसता के शिंकजे को तोड़ते हुए नकली राष्ट्रवादियों से राष्ट्र और संविधान बचाने के लिए सता के खिलाफ मजबूती से खड़ी हो गई।

उन्होंनें आह्वान किया कि हमें महिलाओं की दृढ़ता से संघर्ष करने की ताकत और खुली हुई व्यापक संभावनाओं को पहचानते हुए आगे के काम चिन्हित करने होंगे। हमें अपने संगठन के परिप्रेक्ष्य को गहराई से आत्मसात करते हुए अपने संघर्षों को ज्यादा तेज व तीखा करना होगा। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने, सदस्यता बढ़ाने, इकाईयों व जिला कमेटियों को सक्रिय करने तथा हर जिले पर वैचारिक रूप से मजबूत व संगठन के लिए ज्यादा समय उपलब्ध युवा कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए काम करना होगा।

राज्य कोषाध्यक्ष राजकुमारी दहिया ने आय–व्यय सम्बधी रिपोर्ट पेश की। संगठन व संघर्ष को आगे कैसे लेकर जाएं, इसके लिए प्रतिनिधियों ने समूह चर्चाएं की। रिपोर्ट पर 17 प्रतिनिधियों ने बहस में हिस्सेदारी की। प्रतिनिधियों ने मंहगाई, खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा व यौन हिंसा, गांवों व शहरों में बढ़ती शराब व नशे की खपत, शिक्षा, स्वास्थ्य, बसों में लड़कियों के लिए बस पास, कॉलेजों में टॉयलेटस, बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों, साम्प्रदायिकता व जातिवाद की चुनौतियों, युवा लड़कियों व आंगनवाड़ी में खाना बनाने वाली मदर ग्रुप की महिलाओं से संबधित समस्याओं आदि मसलों पर बातचीत रखी। प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट में सांगठनिक कार्यों व मुद्दों को अपना समर्थन दिया। राज्य सचिव ने बहस को समाहित करते हुए स्थानीय मुद्दों पर संघर्ष करते हुए ईकाईयों को मजबूत करने, जनप्रभाव के मुताबिक सदस्यता में इजाफा करते हुए संगठन का विस्तार करने, कार्यकर्ताओं की वैचारिक व सांगठनिक मजबूती बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देने, होलटाईमर्स की संख्या बढ़ाने, शराब व नशे खिलाफ, युवा लड़कियों के मुद्दों, महिलाओं पर बढ़ती हिंसा के खिलाफ, खाद्य सुरक्षा व सस्ते राशन की मांग को लेकर सतत अभियान चलाने का आह्वान किया। सचिव की रिपोर्ट व कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट दोनों को ही सम्मेलन

ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। प्रतिनिधि सत्र में अग्निपथ योजना के खिलाफ राज्य उपाध्यक्ष शकुन्तला जाखड़ ने प्रस्ताव रखा जिसका राज्य कमेटी सदस्य जरासो ने सर्मथन किया। प्रस्ताव बिना किसी संशोधन के पारित किया गया। सम्मेलन के दौरान थियेटर आर्ट ग्रुप, करनाल ने बेहतरीन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी ।

परिचय पत्र रिपोर्ट

परिचय पत्र रिपोर्ट राज्य कमेटी सदस्य बलबीर कौर ने रखी। सम्मेलन में 13 जिलों से 196 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रतिनीधियों में से 31 प्रतिशत अनुसुचित, 30 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग, 34 प्रतिश्त सामान्य व 0.026 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय से थे। 27 प्रतिशत प्रतिनीधि अनपढ़ और 50 प्रतिशत घरेलू थी। सम्मेलन में शामिल 69 प्रतिशत प्रतिनीधि 45 साल से कम उम्र की थीं।

नई राज्य कमेटी

सम्मेलन ने 23 सदस्यीय नई राज्य कमेटी का गठन किया जिसमें 3 स्थान रिक्त रखे गए। 9 सदस्यीय सचिवमंडल का चुनाव किया गया। उषा सरोहा को महासचिव, सविता को अध्यक्ष और राजकुमारी को कोषाध्यक्ष चुना गया। जगमति सांगवान, शकुंतला जाखड़ व रामकली जांगड़ा को उपाध्यक्ष, जरासो, अमिता को सहसचिव और बबली लांबा को सचिवमंडल सदस्य चुना गया। जनवरी में त्रिवेंद्रम में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्ड़ल चुना गया। समापन से पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाषिनी अली सहगल ने विशेष बातचीत रखते हुए कहा कि गुजरात एटीएस द्वारा मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी अति निंदनीय है। जाकिया जाफरी द्वारा दायर की गई अपील को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के दुर्भाग्यपूर्ण के फैसले के बाद, गुजरात पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया। इस पुरे समय तीस्ता सीतलवाड़ एक चट्टान की तरह सुश्री जाफरी के साथ खड़ी रही हैं। उनके अनुकरणीय साहस के इन्हीं कार्यों के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जनवादी महिला समिति की प्रत्येक इकाई को इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगीा सम्मेलन ने मांग उठाई कि तीस्ता सीतलवाड व अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज झूठा मामला तुरंत वापस लिया जाए और उत्पीड़न बंद किया जाए। जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय महासचिव मरियम ढवले ने अपने जोशीले वक्तव्य से सम्मेलन का समापन किया। उन्होंने कहा कि इस दौर में औरतों की एकता कायम रखना बहुत कठिन लेकिन बहुत जरूरी है। इसके लिए कार्यक्रताओं व संगठन को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंनें इकाईयों को मजबूत व सक्रिय बनाने पर बल दिया। कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रीय महासचिव मरियम ढवले व उपाध्यक्ष सुभाषिनी अली सहगल ने वांलटियरों की टीम को जोरदार तालियों के बीच सम्मानित किया जिनकी कई महीनों की अथक मेहनत ने सम्मेलन को सफल बनाया। नवनिर्वाचित राज्य महासचिव उषा सरोहा ने करनाल की जनता, जनसंगठनों व सम्मेलन को कामयाब बनाने वाले मित्र संगठनों को दिल से धन्यवाद दिया और उनके प्रयासों की सराहना की। महासचिव ने प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि

जनवादी महिला समिति की प्रत्येक सदस्य व महिलाओं के व्यापक तबकों तक सम्मेलन का संदेश लेकर जाएं। लोगों के बीच रहते हुए तथा काम करते हुए संगठन की पहचान को पुख्ता करें। उन्होनें केंद्रीय कमेटी के आह्वानों बारे बताते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा की मांग को लेकर देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए राष्ट्रपति के नाम मांगपत्र और हस्ताक्षर भेजे जाएंगें। हरियाणा से 20000 हस्ताक्षर इक्कठा करने हैं। हस्ताक्षर अभियान 1 जुलाई को जिला स्तर पर प्रैस कांफ्रेंस करके शुरू किया जाए व 26 जुलाई तक चलाया जाए। हस्ताक्षर अभियान इकाइयों के अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कालेज वह अन्य सार्वजनिक जगहों पर भी किया जाए। केंद्रीय कमेटी का आह्वान है कि बढ़ती हुई मंहगाई व आजीविका के मुद्दों पर 1 से 15 जुलाई के बीच में धरने –प्रदर्शन किए जाएं। हरियाणा में 12 जुलाई को जिला स्तर पर धरना–प्रदर्शन करने किए जाएं। धरना –प्रदर्शनों में खाली बर्तन, चकला–बेलन आदि लेकर भी किए जा सकते हैं। 23 जुलाई को कैप्टन लक्ष्मी सहगल के स्मृति दिवस पर जिला स्तर पर आजादी की 75 वीं वर्षगांठ और महिलाओं की भूमिका विषय के इर्द–गिर्द सेमिनार व अन्य कार्यक्रम किए जाएं। इन कार्यक्रमों में स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की महिलाओं को शामिल किया जाए। जिला स्तर पर स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं की जानकारी भी जुटाई जाए। असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जुटाया जाए। प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ व पत्रकार जुबेर रिजवी की गिरफ्तारी के खिलाफ अन्य जन संगठनों के साथ मिलकर प्रदर्शन किए जाएं। सदस्यता अभियान जल्द से जल्द शुरू करते हुए आगामी दो महीनों में 50 प्रतिशत सदस्यता पुरी की जाए। सम्मेलन का समापन विभिन्न जिलों से आए हुए प्रतिनिधियों ने नाच गाकर किया।

भोपाल में अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क सम्मेलन

लोकतंत्र का अर्थ है सभी के लिए समान अवसर, एक बेहतर जीवन और एक सभ्य समाज – केके. शैलजा

आशा मिश्रा बनी एआईपीएसएन की नई महासचिव

भोपाल में 6 से 9 जून तक चार दिवसीय 17 वीं अखिल भारतीय जन विज्ञान कांग्रेस का आयोजन एक भव्य कार्यक्रम में किया गया। इसमें पूरे देश से करीब 800 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वार्ता, चर्चा और संकल्प समारोह के उद्घाटन सत्र में सम्मेलन के कई सत्रों की नींव रखी गई जो अगले चार दिनों तक चले।

उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ताओं में केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा, जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने और जीतने की दुनिया भर में एक उदाहरण स्थापित किया, एक वरिष्ठ पत्रकार और कार्यकर्ता, जिनका कई अंतरराष्ट्रीय सम्मानों के साथ स्वागत किया गया है पी साईनाथ और प्रसिद्ध वैज्ञानिक और गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई की प्रोफेसर डी इंदुमती थे। कार्यक्रम का उद्घाटन मंच से भारत के संविधान के प्रस्तावना और प्रतिभागियों द्वारा ध्वज लहराते हुए किया गया। ये रंग–बिरंगे झंडे भारत की विविधता और बहुलता को दर्शाते थे।

उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के. के. शैलजा ने कहा कि बिना समानता, सभी को अवसर, आजीविका के बिना सही मायने में लोकतंत्र नहीं है। आज पूंजीवादी और सामंती व्यवस्था का समय है। इससे छुटकारा पाने और वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि संविधान बनाते समय जो प्रगतिशील विचार अपनाए गए थे और उन्होंने अखंडता, समानता, समानता और समाजवाद के बारे में बात की थी। हम आज उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बिना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि केरल ने कोविड के समय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इसका सामना किया था। के के शैलजा ने कोविड के समय के अपने अनुभवों को भी साझा किया। गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई के प्रोफेसर डी इंदुमती ने कहा कि उच्च शिक्षा में 6 प्रतिशत की जगह बजट का 0.6 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है, जिसके कारण विज्ञान में शोध के अवसर कम हो गए हैं। प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने पक्षपाती मीडिया के बारे में बात की। इस अवसर पर वरिष्ठ कवि राजेश जोशी, वरिष्ठ साहित्यकार राम प्रकाश त्रिपाठी, अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क के अध्यक्ष डॉ. इस शुरुआती सत्र में सब्यसाची चटर्जी ने भी अपनी बात रखी।

पीपुल्ससाइंस कांग्रेस में देश के लगभग 20 राज्यों के 800 से अधिक वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ''आइडिया ऑफ इंडिया'' साइंटिफिक टेम्पर, आत्मनिर्भरता और विकास सहित कई विषयों पर सेमिनार, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

दूसरे दिन सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रो सोनाझरिया मिंज, शिमला के सामाजिक कार्यकर्ता डॉ ओपी, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव के प्रोफेसर एन रघुराम ने शिक्षा, पर्यावरण और कृषि कृषि के विषयों पर बात की   ।

तीसरे दिन एआईपीएसएन ने स्वास्थ्य, शिक्षा, निजीकरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इसके साथ ही छोटे–छोटे समूहों में विज्ञान और सामाजिक विकास से जुड़े विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अनीता रामपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में कई खामियां हैं, जो लोगों के एक बड़े वर्ग को शिक्षा से वंचित कर सकती हैं। साइंस डॉक्यूमेंट्री निर्माता और वैज्ञानिक गौहर रजा ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन लोगों तक भी पहुंचे, जिन तक विज्ञान पहुंचता है। वरिष्ठ स्वास्थ्य कार्यकर्ता समीर गर्ग ने कहा कि आयुष्मान कार्ड जैसी योजना निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को लाभ पहुंचा रही है और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को कमजोर कर रही है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ। सत्यजीत रथ ने कहा कि महामारी या सामान्य समय में भी दवाओं के साथ–साथ इसकी जानकारी के साथ हम तक पहुंचना जरूरी है। इस दिन अन्य वक्ताओं में प्रोफेसर सुरजीत मजूमदार, पूर्व भारद्वाज, प्रो आर. रामानुजन, प्रो विनीता, प्रो डी इंदुमती, मयंक वाहिया, गौहर रजा, किशोर चंद्र, विवेक मोंटेरो, प्रो. सत्यजीत रथ, समीर गर्ग, इंदिरा चक्रवर्ती, वंदना प्रसाद, टी. सुंदररमन, दिनेश अबरोल, अशोक धवले और देश के कई वरिष्ठ वैज्ञानिक, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे।

अन्य छोटी कार्यशालाओं में, विभिन्न राज्यों के जमीनी कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभवों को साझा किया। हर शाम, विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक प्रदर्शन किए। समारोह स्थल पर विभिन्न राज्यों की पुस्तकों और उत्पादों के स्टाल लगाए गएं। वरिष्ठ चित्रकार मनोज कुलकर्णी की एक पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विचार पर विभिन्न महापुरुषों और वैज्ञानिकों के बयानों को दर्शाया गया था। एआईपीएसएन के समापन सत्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विकास पर रोचक चर्चा हुई। इस सत्र के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव शरद चंद्र बेहार ने कहा कि मार्क्स ने कभी धर्म को अफीम के रूप में वर्णित किया था – उसी तर्ज पर,'' विकास'' आज नई अफीम है। इस सत्र में उद्योग विशेषज्ञ राजेंदर कोठारी, अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज ने भी अन्य वक्ताओं के साथ विचार रखे।

इन चार दिनों के सम्मेलन में रोज दो तीन पुस्तकों का विमोचन होता रहा जो जनता के जीवन से जुडे मुद्‌दों पर किये गये कामों और समाज में वैज्ञानिक चेनता बढाने के लिये

किये जा रहे कामों और आवश्यक कामों के बारे में विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं के द्वारा लिखी गयी हैं।

एआईपीएसएन में महिलाएं

एआईपीएसएन के सम्मेलन में महिलाओं की उपस्थिति प्रभावी रही। एडवा की सीईसी सदस्य और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मैमुना अब्बास मोल्लाह ने भी प्रतिनिधियों को संबोधित किया और कहा कि वर्तमान सरकार अल्पसंख्यकों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक समर्थकों को बेक कर रही है जो वास्तव में संघ परिवार से संबंधित हैं और वैज्ञानिक शिक्षा और चेतना को बढ़ावा देने के बजाय वे लोगों को कट्टरता की ओर धकेल रहे हैं, कट्टरवाद और अंधविश्वास। उन्होंने समाज में महिलाओं की तीन भूमिकाओं और उनकी हर भूमिका में उनके द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के बारे में बात की।

स्वास्थ्य पर संगोष्ठी में मप्र एडवा की प्रदेश संयुक्त सचिव रीना शाक्य ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अक्सर मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता की जानकारी की कमी के कारण कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके अलावा कई लड़कियों को पीरियड्स के दौरान कठिनाइयों के कारण स्कूल छोड़ना पड़ता है। शिक्षा पर संगोष्ठी में उन्होंने सावित्रीबाई फुले के नाम से पाठशाला या लर्निंग सेंटर के बारे में बताया सम्मेलन के तीसरे दिन एडवा की प्रदेश संयुक्त सचिव प्रीति सिंह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने एडवा इकाइयों द्वारा संचालित परामर्श केंद्रों के बारे में बात की। इस विशेष सत्र का संचालन मध्य प्रदेश एडवा की जबलपुर इकाई की अंजना कुररिया और बिहार की एडवा की नेत्री पुष्पा ने किया।

समापन समारोह में मुख्य अतिथि रहे संविधान विशेषज्ञ और हैदराबाद की लॉ युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा ने कहा कि कानून का मतलब न्याय है, लेकिन आज हालात यह है कि लोगों के लिए क्या न्याय है, यह बताना मुश्किल हो गया है। लेकिन समस्या यह है कि हमें अन्याय भी नहीं दिखता है। हम किसी के साथ हो रहे अन्याय से विचलित क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मानवता पर सवालिया निशान लग गया है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है। इसका मतलब साफ है कि जो कुछ भी व्यक्ति के दिल में है, उसे बोलने दें। जो समाज इसे बोलने से रोकता है, वह आगे नहीं बढ़ सकता है। जनता की सहमति से सरकार हो तो सरकार की नीतियों पर बोलकर ही जनता की भागीदारी हो सकती है। यह आलोचना के रूप में भी ज्यादा प्रशंसा हो सकती है। उन्होंने कहा कि देश में वैज्ञानिक चेतना के बिना देश को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। देश में हेट स्पीच के खिलाफ कड़े कानून बनाने की जरूरत है। आज देश में धर्म, सत्ता और कॉरपोरेट का गठजोड़ है, अगर हम इसे समझ लें तो कुछ बेहतर करना संभव है। प्रोफेसर। आर रामानुजम, सिद्धु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोनाझरिया मिंज ने वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाने की आवश्यकता के बारे में भी बताया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज देश में जो कट्टरता फैली है, उसे वैज्ञानिक चेतना से ही खत्म किया जा सकता है।

चार दिवसीय सम्मेलन का समापन करते हुए एआईपीएसएन के नए नेतृत्व का चुनाव किया गया। एआईएसईआर पुणे के वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्यजीत रथ को अध्यक्ष के रूप में, एमपी बीजीवीएस की आशा मिश्रा को महासचिव के रूप में और मध्य प्रदेश विज्ञान सभा के एस आर आजाद को कोषाध्यक्ष के रूप में 9 पदाधिकारियों और 22 कार्यकारिणी सदस्यों के साथ चुना गया है। एआईपीएसएन ने विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों से 10 आमंत्रितों को भी अपनी कार्यकारिणी के लिये चुना।

नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम ..

उप्र एडवा का सद्भावना अभियान

मधु गर्ग

''सात संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसा को मोहब्बत की जरूरत है बहुत''

यह पैगाम लेकर एडवा उप्र की बहनें बस्तियों और मोहल्लों में सद्भावना फेरी निकाल रहीं हैं, और नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम दे रहीं हैं। आज के माहौल में यह एक बेहद जरूरी पहल है।

देश भर में नफरत की आग लगाई जा रही है और उसका चौम्पियन उप्र बना हुआ है। उप्र में मुख्यमंत्री योगी बाबाजी जिन्हें अब बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, अपने तानाशाही फरमानों से एक समुदाय को सबक सिखाते रहते हैं। देश भर में नवरात्रि और रामनवमी से चलाये गये इस नफरती अभियान में जानबूझकर अजान बनाम हनुमान चालीसा या लाउडस्पीकरों को विवाद का मुद्दा बनाया गया। भगवा झंडे मस्जिदों पर फहराये गये, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से जुलूस निकालकर भड़काऊ नारे लगाए गये। इस नफरती अभियान का स्पष्ट संदेश था कि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी ''औकात''में रहे, यह देश केवल हिंदुओं का है। हिंदुत्व वादी गिरोहों, जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत देश में नफरत की आग लगाकर दो समुदायों के बीच गहरी खाई बना रहे हैं। ये गिरोह और इनकी विचारधारा सत्ता पर भी काबिज है तो पुलिस प्रशासन भी इनके इशारों पर काम करता है, जिसका खामियाजा भी एक विशेष समुदाय को आये दिन झेलना पड़ता है। इस समुदाय के नौजवान बच्चे संदेह के आधार पर ही जेल भेजे जा रहे हैं, पुलिस यातनाओं का शिकार हो रहे हैं। इस स्थिति में इस विशेष समुदाय की असुरक्षा और अलगाव के दर्द को समझा जा सकता है। इस दर्द पर मरहम लगाने की जरूरत है, उनके खोये हुए भरोसे को फिर से वापस लाने की जरूरत है। उनसे यह कहने की जरूरत है कि ''बंदे एक खुदाय के हिंदू मुसलमान, दावा राम रसूल कर ,लड़ दे बेईमान''। गुरु नानक का यह संदेश दे रहीं हैं जनवादी महिला समिति की बहनें ..

इसी प्रकार बहुसंख्यक समुदाय, जो अपनी साझी विरासत व संघर्षों को भूलता जा रहा है, उसे भी इतिहास के उन पन्नों को याद दिलाने की जरूरत है जो साझे संघर्षों को बयान करते हैं। बहुसंख्यक समुदाय के बीच जानबूझकर झूठ फैलाकर उन्हें नफरत की दलदल में घसीटा जा रहा है, और इस प्रकार का नैरेटिव देश में गढ़ दिया गया है कि जनता के बुनियादी मुद्दे रोजी रोटी स्वास्थ्य शिक्षा मंहगाई सब पीछे होते जा रहे हैं। गैस सिलिंडर

1100 रुपये और आटा 30 रुपये किलो बिक रहा है । इन सबके बीच चुपचाप देश की संपत्ति बिक रही है। कारपोरेट और हिंदुत्व का गठजोड़ बहुत भयानक खेल खेल रहा है।

इस साजिश का पर्दाफाश करने और जनता के बीच मोहब्बत का पैगाम देने के साथ उन्हें अपनी समृद्ध साझी संस्कृति व संघर्षों को याद दिलाने के लिए लखनऊ में तमाम बस्तियों और मोहल्लों में सद्भावना फेरी निकाली जा रहीं हैं। कानपुर में बाजारों और मोहल्लों में पर्चे बांटे जा रहे हैं।

हम अपने पर्चों के माध्यम से बता रहे हैं कि आजादी की लड़ाई में यदि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की कमान संभाली तो बेगम हजरत महल की तलवार ने भी ब्रिटिश फौज का सामना किया। भगतसिंह लाहौर की जेल में तो अश्फाकउल्ला फैजाबाद की जेल में फांसी पर झूल गये। ''सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा'' अल्लामा इक़बाल ने लिखा तो ''बंदे मातरम'' की रचना बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने की। हमारे देश में साझी विरासत और परंपराओं की तमाम मिसालें हैं, जैसे लखनऊ का प्रसिद्द हनुमान मंदिर अवध के नवाबों द्वारा बनवाया गया और आज भी मंदिर पर चांद का निशान उस साझी विरासत की याद दिलाता है। होली के रंगों में जहां मुसलमान सरोबार हुए तो हिंदुओं ने मजारों और ताजियों पर मन्नतें मांगी। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में हिंदुस्तानी फौजें लड़ीं जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों ही थे। इस विद्रोह की अगुवाई के लिए मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को चुना गया।

सद्भावना फेरी के दौरान छोटी नुक्कड़ सभाओं में एडवा के नेताओं ने बताया कि जनता को गलत इतिहास बताकर भ्रमित किया जा रहा है। हिंदू राजा की सेना में मुस्लिम सेनापति रहे तो मुगल बादशाह की सेना व दरबार में उनके विश्वासपात्र हिंदू रहे।

हमारे देश की परंपराओं के विविध रंग ही तो हमारे देश को खूबसूरत बनाते हैं। अमीर खुसरो का गीत '' काहे को ब्याहे बिदेस '' बेटी की विदाई में हिंदू मुसलमान दोनों को ही रुलाता है। सूरदास और रसखान की कृष्ण भक्ति को अलग करके कैसे देखा जा सकता है। महाकाव्य रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने मस्जिद से कभी बैर नहीं किया और कहा कि ''मांग के खइबो, मजीद में सोइबो'' और वहीं ये नकली राम भक्त मस्जिद का अपमान कर रहे हैं। हिंदुस्तान विविधताओं का देश है। तमाम संस्कृतियां यहां आईं और यहां घुलमिल गईं। खानपान में भी यह साझापन दिखाई देता है जैसे ''हलवा जलेबी '' जिसका मंदिरों में प्रसाद लगता है वह मुगलों द्वारा भारत में लाया गये व्यंजन हैं। एडवा ने अपने पर्चों और भाषणों के माध्यम से घर घर यह संदेश पहुंचाया कि हिंदुस्तान विभिन्न रंगों, संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का ख़ूबसूरत देश है जिसे एक रंग में रंगने की साजिश दरअसल इसकी आत्मा पर चोट है। इस अभियान के तहत पर्चे बांटने के साथ साथ सद्भावना व एकता का संदेश देते हुए स्टिकर भी दुकानों और घरों के दरवाजों पर चिपकाये गये। उनमें संदेश था '' छेड़िए एक जंग गरीबी के खिलाफ मेरे दोस्त, कुर्सी के लिए मजहबी नगमात

को मत छेड़िए '' अदम गोंडवी का यह शेर आज के हालात का बयान करता है। इसी प्रकार कैफी आजमी, बशीर बद्र, फैज अहमद फैज की नज्मों की लाइनें लिखीं हुईं थीं जो एकता और सद्भावना का संदेश दे रहीं थीं।

सद्भावना फेरी का 11 मई से आरंभ हुआ, यह अभियान अभी 23 जुलाई तक चलेगा। लखनऊ में अभी तक 20 बस्तियों में यह अभियान चलाया जा चुका है। हर मोहल्ले और बस्ती में बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हमारे नारे उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं और उनकी आंखों में जो भरोसे का भाव दिखता है वही हमारे अभियान की सफलता है। हमारा यह भी अनुभव रहा कि मुस्लिम समुदाय में जबरदस्त भय और असुरक्षा का भाव आ गया है, जब वे हमें अपना समझ लेते हैं तो अपना दर्द बहुत खुल कर व्यक्त करते हैं। हिंदू बस्तियों में भी आम जनता सत्ता की साजिश को समझ रही है। मंहगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है।

अभियान के दौरान हमें कई बार तिलकधारियों को देखकर लगा कि ये हमें कुछ गलत बोल सकते हैं किन्तु जब वे मांगकर स्टिकर अपनी दुकान पर लगाने लगे और हमारे साथ ही नारे लगाने लगे तो धारणा बदल गई। कई मोहल्लों में हमारे जुलूस पर फूल भी बरसाये गये जो अद्भुत अनुभव था।

दलित बस्तियों में एक अलग अनुभव रहा। उनका कहना था कि आप लोग मुसलमानों के खिलाफ हमलों को देख रहे हैं किन्तु यह हमला अब हमारे ऊपर भी है। हमें अब महसूस हो रहा है कि अब हम फिर से पीछे जा रहे हैं और जो दर्द हमारी पुरखों ने सहा , अब फिर वही समय वापस आ रहा है।

इस नफरत की आंधी में कोई नहीं बचेगा यदि इसे यहीं पक्के इरादों के साथ रोका नहीं गया।

'रेत समाधि' – एक उपन्यास जो सीमाओं को तोड़ता है

मनजीत राठी

हाल ही मे, वर्ष 2022 में, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित, गीतांजलि श्री का पांचवां उपन्यास रेत समाधि, (एक अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल द्वारा *"Tomb of Sand"* के रूप में अंग्रेजी में अनुवादित), (पेंगुइन रैंडम हाउस, 2022), मूल रूप से वर्ष 2018 में हिंदी में लिखा गया। यह किसी भी भारतीय भाषा में लिखी पहली पुस्तक है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। 1957 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी शहर में जन्मी, और वर्तमान में नई दिल्ली में रह रही , गीतांजलि श्री हिंदी साहित्य में व्यापक रूप से जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने पांच उपन्यास और लघु कथाओं के कई संग्रह लिखे हैं। कथा साहित्य के अलावा, उन्होंने मुंशी प्रेमचंद पर महत्वपूर्ण रचनाएँ भी लिखी हैं। 2000 में उनका पहला उपन्यास, माई, 2001 में क्रॉसवर्ड बुक पुरस्कार के लिए चुना गया था और अंग्रेजी, उर्दू, सर्बियाई, कोरियाई, फ्रेंच और जर्मन सहित कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है।

इस उपन्यास के बारे मे अनुवादक डेजी रॉकवेल की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है कि, "यह न केवल अपनी लंबाई (696 पृष्ठों और तीन भागों मे बँटी) में एक विशाल पुस्तक है, बल्कि इसका दायरा भी व्यापक है और मुद्दों की जटिलता भी। इसे मोटे तौर पर परिवारों, मां–बेटी के रिश्तों और भारत और पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित जटिलताओं से निपटने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लेकिन सबसे बढ़कर, यह सीमाओं और दीवारों के बारे में, और भाषा की सुंदरता और पेचीदगियों के बारे में है, विशेष रूप से हिंदी भाषा की गूढ़ता

के बारे में"। लेखक, गीतांजलि श्री, ने भाषा की इस पेचीदगी का, बुकर पुरस्कार की स्वीकृति के अपने भाषण के दौरान, कुछ इस तरह वर्णन किया हैः ''मुझे लगता है कि सभी भाषाओं में सीमाओं को पार करने और शब्दों को फिर से खोजने, शब्दों को उधार लेने, और शब्दों के साथ खेल करने और साहसिक होने की संभावना है। यह संभावना अंग्रेजी भाषा मे भी उतनी ही है, जितना की हिंदी मे ... और जैसा कि हम हिंदी के बारे में कहते हैं, कोई एक हिंदी नहीं हैय इतनी सारी प्रकार की हिंदी हैं। अंग्रेजी के बारे में भी यही कहा जा सकता है।'' (बुकर पुरस्कार स्वीकृति भाषण)

यह उपन्यास केवल लेखक या किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। यह ''हिंदी साहित्य की पूरी दुनिया और समग्र रूप से भारतीय साहित्य'' की बड़ी तस्वीर का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास है। उत्तर भारत की पृष्ठभूमि मे लिखे गए इस उपन्यास की शुरुआत एक अस्सी वर्षीय भारतीय महिला ('मां') के साथ होती है जो अपने पति की मृत्यु के बाद अवसाद, खालीपन और एक समाधि जैसी जीवन शैली में प्रवेश कर चुकी है। परिवार का प्रत्येक सदस्य उसकी समाधि जैसी सी ध्यान अवस्था को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं होताः "अस्सी की होने चली दादी ने विधवा होकर परिवार से पीठ कर खटिया पकड़ ली। परिवार उसे वापस अपने बीच खींचने में लगा। प्रेम, वैर, आपसी नोकझोंक में खदबदाता संयुक्त परिवार। दादी ने जि़द कि अब नहीं उठूँगी। फिर इन्हीं शब्दों की ध्वनि बदलकर हो जाती है अब तो नई ही उठूँगी। दादी उठती है। बिलकुल नई"। (रेत समाधि)

(हम भाग 1 मे उनके बेटे 'बड़े' से मिलते हैं, जो माँ से चेक बुक पर हस्ताक्षर करवाने के बारे में अधिक चिंतित हैंय 'बड़े' की पत्नी 'बहू' से परिचित होते हैं, जो रीबॉक पहनती है और महसूस करती है कि कोई भी उसके बलिदान का सम्मान नहीं करता है, और उनके दो पोते हैंः 'सन' और 'सिड'। (भाग 1) भाग ⅠⅠ में माँ अपने जीवन को नई तरह से देखना शुरू करती है। यह नया–नया उत्साह उसकी बेटी को विचलित करता है, जो अपनी माँ (मा) का यह रूप देखने की आदि नहीं है, और इसे समझ नहीं पाती है। मामलों को और भी पेचीदा बनाने के लिए, भाग ⅠⅠⅠ में 'मां' पाकिस्तान जाने पर जोर देती है, ताकि उस आघात का सामना कर सके, जिससे उसे एक किशोरी के रूप में, विभाजन के भयानक कोलाहल के समय गुजरना पड़ा था।

लेखिका, हालांकि, केंद्रीय चरित्र, 'मां' के दुःख पर ठहरने के बजाय, कथा के लहजे को हल्का रखती है, क्योंकि वह अनसुलझे आघात, नारीवाद, विभाजन और मातृत्व जैसे कठिन मुद्दों के आसपास महत्वपूर्ण प्रश्नों को संबोधित करना चाहती है, विशेष रूप से इस सवाल को, कि मौजूदा समय मे एक महिला होने के क्या अर्थ हैं? जाहिर है कि ऐसे पेचीदा सवालों के जवाब कभी भी पूर्ण या अंतिम नहीं माने जा सकते है। 'मां' जैसा चरित्र को गढ़ने में लेखिका न केवल सरहदों और सीमाओं को पार करती है, वह संभावनाओं की ऐसी दुनिया बुनती है जहां कुछ भी अपवाद नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है।

यह उपन्यास अनेक तरीकों से, दक्षिण एशिया में कहानी कहने के समृद्ध इतिहास का प्रतीक है, और किसी भी प्रकार के वर्गीकरण से परे है। 'मा' के केंद्रीय चरित्र के अलावा, दो 'अन्य' महिलाएं हैं: (1) 'बेटी' – परिवार को शर्मसार करने वाली भगोड़ा बेटी, वह एक स्वतंत्र, नारीवादी और महिला अधिकार कार्यकर्ता है, और (2) रोजी – एक हिजड़ा , हर तरह से 'अन्य'। इस कहानी में रोजी का आना सीमाओं के स्थानांतरण का संकेत देता है, क्योंकि जल्द ही 'मा' पाकिस्तान जाने की इच्छा व्यक्त करती है और, उसकी उम्र को देखते हुए, माँ का परिवार उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है। साथ ही, परिवार चिंतित भी है, कि क्या 'मा' की इच्छा की खातिर, हर किसी के जीवन को खतरे में डालकर सीमा पार करना उचित रहेगा?

गीतांजलि श्री मानती हैं कि इस उपन्यास की कोई 'एक' कहानी नहीं है। इसके हर पन्ने पर एक नई कहानी जन्म लेती है। इसमें हर पैराग्राफ में एक नया किरदार प्रवेश करता है और अपना किस्सा सुनाने लगता है। निर्जीव चीजें भी इसमें जीवंत हो उठती हैं, और अपना–अपना किस्सा सुनाने लग जाती हैं। घर का दरवाजा, दीवारें, छड़ी, पेड़–पौधे, पंछी–तितलियां और यहां तक की रेत और हवा भी। लेखिका का यह भी मानना है कि हर करने योग्य काम सीमाओं से परे होता है। और इसलिए, मा ने अपनी बेटी के साथ सीमा पार की और वह भी बिना वीजा के, क्योंकि वह उसी रास्ते आई थी: "और कौन उसे बता सकता है कि वह कहाँ है: यहाँ या वहाँ? क्या उसे सीमा पार करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता है क्योंकि दो सरकारों ने एक रेखा खींचने का फैसला किया है? (रेत समाधी) जब भी पाकिस्तान में निरीक्षकों और अधिकारियों द्वारा माँ से उसके ठिकाने के बारे में पूछा जाता है, तो वह हास्य और व्यंग्यात्मक प्रतिक्रियाएँ देती रहती है।

यह उपन्यास पितृसत्ता, पुरुषत्व, नारीवाद , विभाजन की राजनीति, सांप्रदायिकता, ट्रांस्जेंडर मुद्दों की पृष्ठभूमि मे, औरत के दुख दर्द के आंतरिककरण, उसकी इच्छाओं और पसंद नापसंद से उपजने वाले द्वंद्वों और टकरावों को अंदर और बाहर से देखने का एक प्रयास है, जो ''बूढ़ी उम्र'' की फिर से जांच करने, 'दूसरे' के प्रति सहिष्णु होने, अपनी पसंद का सम्मान करने के लिए, वास्तविकता को नए सिरे से देखने के लिए, और सबसे बढ़कर, साहित्य में विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है। लेखिका यह उपन्यास कृष्णा सोबती को समर्पित करती हैं: ''मेरे गुरु के लिए, मेरी प्रेरणा, मेरी प्रिय कृष्णा सोबती।''

खेल और विश्व विजेता निखत

जगमती सांगवान

वैसे तो पितृसत्तात्मक समाजों में सभी महिला खिलाड़ियों को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना होता है । परंतु जब प दलित व फिर उसके बाद अगर मुस्लिम समुदाय से महिला खिलाड़ी हो तो ये बाधाएं अति विकराल रूप में उनके रास्ते रोकती हैं । इसीलिए तमाम संवेदनशील खेल विशेषज्ञ इन तबकों से आने वाली महिला खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रोत्साहनों की सिफारिश करते हैं ।इन हालात में निजामाबाद (हैदराबाद)की मुस्लिम महिला खिलाड़ी निखत ने एक के बाद एक जिस तरह विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल जीते हैं वह अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है । लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश को निखत को विश्व विजेता के रूप में जिस प्रकार सिर आंखों पर बैठाना चाहिए था ,उस आलम को देखने के लिए आंखें तरसती ही रह गई ।क्योंकि एक भीम अवॉर्डी खिलाड़ी व खेल विशेषज्ञ होने के नाते मैं आसानी से कल्पना कर सकती हूं कि निखत के पाले में सकारात्मक तो कुछ भी नहीं था और नकारात्मक जो कुछ भी संभव हो सकता है वह सब कुछ था। ऐसी परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सिर नीचा व स्वयं को ऊंचा करने के लिए वास्तव में 58 इंची सीना ही नहीं बल्कि एक लो संकल्प भी चाहिए। जिसे किसी भी बाधा से डरने व हिलने की इजाजत ना हो । निखत उस व्यक्तित्व की मालिक है । यह उसने अपनी उपलब्धियों के माध्यम से स्थापित किया है । इस व्यक्तित्व को तमाम सम्मानों से नवाजने में 56 इंची सीने वाले मुंह क्यों छुपा रहे हैं। इसका अंदाजा भी लगाया जाना चाहिए और उस प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज भी बुलंद होनी चाहिए ।तमाम संवेदनशील संस्थाओं को भी निखत की इस विजय को प्राथमिकता पर सम्मानित करना चाहिए ।ताकि अनेकों निखत जो अपने खिलाड़ी बनने के सपनों को मजबूरी वश दबाए बैठी हैं उनके भी सपने साकार होने के रास्ते खुलें ।

कोई यह भी कह सकता है कि सानिया मिर्जा ने भी खेलो मैं ऐसी ही सफलता हासिल की थी । लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि खेलों का चरित्र भी वर्गीय होता है । कुछ खेल कुलीनों के व कुछ गरीब लोगों के होते हैं । बॉक्सिंग दूसरी श्रेणी में आता है। जाहिराना तौर पर सानिया मिर्जा ने भी अवश्य बाधाओं का सामना किया होगा परंतु निखत का संघर्ष ज्यादा हीरों जड़ा है ।

14 जून 1996 को निजामाबाद में जन्मी निखत ने सबसे पहले गुवाहाटी में हुई दूसरी अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग चौंपियनशिप में मेडल जीता। उसके बाद 2011 में जूनियर महिला एवं युवा विश्व चौंपियनशिप अंटालिया में स्वर्ण पदक जीता ।अभी 2022 में उसने आईबीए सरीखी महिला विश्व प्रतियोगिता मैं गोल्ड मेडल जीता है । उसके तुरंत बाद निखत ने हिजाब

पर छिड़ी बहस में महिलाओं की अपनी पसंद के सम्मान की पक्षधरता कि व माना कि उसने स्वयं बहुत सारे पूर्वाग्रहों का सामना किया गया है।

खेल क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के मुकाबले लैंगिक आधार पर भेदभाव की नजर से महिला आंदोलन के बीच कम चर्चा का विषय रहा है। जिसे मुख्यधारा की चर्चा में शामिल करने की जरूरत है। क्योंकि पिछले ही महीने देश की चोटी की साइकिलिंग खिलाड़ियों के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर की टूर्नामेंट के दौरान उन्हीं के ऑफिशियलस के द्वारा यौन हिंसा की शिकायत उन्होंने की । जिसकी वजह से पूरी टीम को तुरंत वापस वतन बुलाना पड़ा । वर्तमान में खेलों में महिलाओं की भागीदारी भी निरन्तर बढ रही है ।